कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेतम) :

(क) से (ग) सरकार द्वारा तैयार किए गए कृषि नीति संकल्प के संशोधित मसौदे में यह व्यवस्था की गई है कि "सरकार, कृषि को उद्योग के समान दर्जा देने के लिए एक सकारात्मक व्यापार तथा निवेश संबंधी वातावरण का सृजन करने का प्रयास करेगी । सरकार की नीति का उद्देश्य, प्रभावकारी प्रणालियों को विकसित करना तथा कृषि पर उद्योग के समान लाभ प्रदान करना होगा" संकल्प का संशोधित मसौदा 14 मई, 1993 को सभा पटल पर रखा गया है ।

DEMAND OF FRUITS, VEGETABLES AND MEAT ETC. IN GULF COUNTRIES

3315. SHRI BHUPINDER SINGH MANN : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is an acute demand in Gulf countries of fresh fruits, vegetables, meat etc. ;

(b) if so, whether Government have any plan to help the farmers to enter the Gulf-market ;

(c) if so, the details thereof ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI S. KRISHNA KUMAR) : (a) to (d) The Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

SUPPORT TO BASMATI RICE GROWERS

3316. SHRI BHUPINDER SINGH MANN : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government are aware that prices of Basmati rice have dwindled to all time low ;

(c) what steps Government propose to take to support the Basmati rice growers ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM) : (a) and (b) The Wholesale Prices of Basmati Rice have recently shown a downward trend. This may be attributed to the commencement of kharif marketing season with effect from October, 1993.

(c) The minimum support prices fixed for fine and superfiine varieties for 1993-94 paddy crop are Rs. 330 and Rs. 350 per quintal as compared to Rs. 280 and Rs. 290 per quintal respectively for the 1992-93 crop. Resides, export of Basmati Rice has also been allowed.

NEW VARIETIES OF COTTON AND RICE BY PAU, LUDHIANA

3317. SHRI VIRENDRA KATARIA : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that no new variety has been evolved in cotton, rice wheat by Punjab Agriculture University at Ludhiana and that the University research work is at stand still, if so, the reasons thereof and if not, the varieties developed by the University, cropwise ; and

(b) whether the cane cultivation is on the decline in Punjab and many Sugar Mills like Fazilka Co-op. Sugar Mills is not getting enough Sugarcane from the area if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI S. KRISHNA KUMAR) : (a) No, Sir. The varieties

developed by the Punjab Agricultural University in cotton, rice and wheat are as follows :—

1. Cotton :—American Cotton—J 34, J 205, F 414, LH 372, F 286, LH 900, F 505, LH 866.

   Desi Cotton—G 227, LD 133, LD 230, LD 327.
   Hybrid Cotton—Fateh.

2. Rice :—PR 4141, Punjab Basmati-1, PR 108, PR 109, PR 110 and Basmati 385.

3. Wheat :—PBW 12, WL 711, WL 1562, WL 2265, PBW 65, PBW 138, PBW 154, PBW 175, PBW 226 and PBW 299.

(b) The area under sugarcane in Punjab varies from year to year and it rotates around 1 lakh hectares. However, sugercane crushed during 1990-91, 1991-92, and 1992-93 was 3102000, 4173000 and 4351000 tonnes, respectively. Those sugar factories which have limited irrigation facility experience lack of sufficient cane for entire crushing period. The Fazilka Co-operative Sugar Mills has crushed 195000, 233000, 103000 tonnes during 1990-91, 1991-92 and 1992-93 seasons, respectively. The sugarcane average depends on price and other factors.

देश में खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता

3318. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**
डा. जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या कृषि मंत्री 10 दिसम्बर, 1993 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 1070 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गरीबी उन्मूलन, बेरोजगारी को समाप्त करने और देश के ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए आगामी 15 वर्षों में वर्तमान कृषि उत्पादन को दुगना करने की भारी आवश्यकता है;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या विचार है; और

(ग) क्या सरकार देश की कृषि नीति में ऐसे प्रोत्साहनों की घोषणा करेगी ताकि उससे आर्थिक विषमता से त्रस्त किसान वर्ग को लाभान्वित किया जा सके और यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या योजना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग) सरकार की कृषि नीति का लक्ष्य बढ़ती हुई आबादी हेतु खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृषि उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना है। विभिन्न फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता देने के लिए गेहूं, मक्का और कदन्न हेतु विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम, एकीकृत चावल विकास कार्यक्रम, गहन कपास विकास कार्यक्रम और विशेष पटसन विकास कार्यक्रम राज्यों के कृषि विभागों के जरिए अभिज्ञात राज्यों में कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इन योजनाओं के जरिए नई किस्मों, सूक्ष्म पोषकों, पर्यावरण-सह कृमिनाशियों, पादप रक्षण उपस्करों, उन्नत कृषि उपकरणों आदि की वृद्धि करने के लिए किसानों को प्रेरित करने हेतु प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। इसके अलावा तकनोलॉजी के प्रभावी अन्तरण के लिए किसानों के खेतों पर क्षेत्रगत प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं तथा किसानों/कृषि मजदूरों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके अलावा नव-विकसित स्थान विशिष्ट उच्च उत्पादक किस्मों के प्रचार के लिए किसानों को नाम मात्र की लागत पर बीजों के मिनिकिट वितरित किए जा रहे हैं।

दूध का उत्पादन

3319. **श्री राम जेठमलानी :**
श्री बोरेन जे. शाह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य 70 मीट्रिक टन रखने का निर्णय किया है;